Seventeenth Loksabha

>

Title: Issue regarding the demand of statehood for a seperate Gorkhaland statehood in Darjieling hilhy area.

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, दार्जिलिंग पहाड़िया, तराई और डूआर के लोगों की लंबे समय से चल रही एक राजनीतिक माँग है, जिसने वर्ष 1986 से 1988, वर्ष 2013 से 2014 और पुन: वर्ष 2017-18 में गोरखालैंड राज्य की माँग का रूप ले लिया । सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए दो बार प्रयास किए । उसने दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल और गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन नामक सेमी ऑटोनोमस बॉडी का गठन करके ये प्रयास किये थे । ये दोनों ही प्रयास यहाँ के लोगों की लंबे समय से चली आ रही अलग राज्य की माँग का स्थायी राजनीतिक समाधान करने में असफल रहे । राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी यह क्षेत्र संवेदनशील है । यह क्षेत्र चिकन नेक क्षेत्र में आता है, जो भारत को पूर्वोत्तर राज्य से जोड़ता है । आज इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध रूप से घुसपैठ हो रही है तथा विकास और आर्थिक प्रगति में भी यह पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है ।

अत: मैं इस सम्माननीय सदन के माध्यम से सरकार से एक बार पुन: अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे तथा इस समस्या का स्थायी राजनीतिक समाधान निकालने के लिए केन्द्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और स्थानीय प्रतिनिधि के बीच त्रिपक्षीय बातचीत शीघ्रता से शुरू की जाए । धन्यवाद ।

माननीय सभापति : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री राजू बिष्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।